उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजना

2062. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि मंजूर की थी, और

(ख) इस वर्ष के दौरान एवं वर्ष 1993-94 तक इन योजनाओं के तहत कितने गांव शामिल किये गये अथवा उन्हें शामिल किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) केन्द्र सरकार ने 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को पेयजल सप्लाई तथा अन्य प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात (1) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (3) जवाहर रोजगार योजना के लिए स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :–

कार्यक्रम	रिलीज की गई राशि (लाख रुपए में)
1. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	5505.00*
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6843.74
3. जवाहर रोजगार योजना	47110.02

*(1) समस्याग्रस्त गांवों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है।

(2) केन्द्र द्वारा योजना/परियोजनावार निधियां रिलीज नहीं की जाती है लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

(ख) 1993-94 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 2487 गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है।

No-Source Category Villages in the Country

2063. SHRI MURIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of no-source category villages, State-Wise ;

(b) the targets set for providing drinking water in No-source cotegory villages during the last three years ;

(c) what has been the performance against the targets ; and

(d) the steps taken by Government to accelerate the pace of providing safe drinking water in all villages ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) The Statewise number of no-source problem villages as on 31-10-93 is as under :

Assam	9
Gujarat	9
Jammu & Kashmir	207
Maharashtra	22
Meghalaya	252
Orissa	16
Rajasthan	47
Tripura	3
Uttar Pradesh	92
TOTAL	657

(b) and (c) The targets set for providing drinking water in No-Sources problem villages an performance against the targets during the last three years is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXIX, Annexure no 50]

(d) The Central Government had allocated special allocation of Rs. 190 crores in 1991-92 and 1992-93 to the concerned States to accelerate the pace of provision of safe drinking water facilities in the remaining No-Source problem villages. The progress of coverage in Non-Source villages is being monitored closerly and rtveiewed from time to time with the various States,